करेंट अफेयर्स राजस्थान

दिसंबर

(संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

राजस्थान **5**

- बीकानेर के नोखा व चूरू के मालासर में लगेंगे बायोमॉस पॉवर प्लांट 5
- ‘बैक टू वर्क’ योजना 5
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 6
- इन्वेस्ट राजस्थान-2022 6
- डॉ. शिवसिंह राठौड़ बने आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष 7
- दिव्यांगजन दिवस पर पोस्टर का विमोचन 7
- उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शिमला में बैठक आयोजित 8
- जिनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि 8
- ओपन थिएटर का शुभारंभ 9
- राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग का शुभारंभ 9
- नागरिक सुरक्षा का 59वाँ स्थापना दिवस मनाया गया 10
- बच्चों में हाइजीन व स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु टाबर सोसायटी के साथ एमओयू 10

नोट :

दृष्टि The Vision

- अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा 11
- एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक 11
- 'राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक'पुस्तक का विमोचन 12
- इन्वेस्ट राजस्थान-2022 मुंबई एवं अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम 12
- चिकित्सा मंत्री ने कैंसर प्रिवेंटिव एंड अर्ली डिटेक्शन मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी 13
- सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योज़ना-2021 14
- राजस्थान पर्यटन एवं वेडिंग डेस्टिनेशन में सर्वश्रेष्ठ 14
- अलवर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला नि:शुल्क टेली मेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र 15
- जयपुर डिस्कॉम का रोड शो 15
- ई-वर्क एवं ई-मैप मोबाईल ऐप 16
- पाँच दिवसीय राष्ट्रीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला प्रारंभ 16
- राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 17
- ऊर्जा मंत्री ने बाँटे राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 17
- इन्वेस्ट राजस्थान-2022: 18
- राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय 19
- ज्ञानदूत 2.0 20

नोट :

- कला एवं संस्कृति मंत्री ने किया 'लोकरंग-2021' का उद्घाटन 20
- रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड-2021 21
- 'आपका विश्वास-हमारा प्रयास' प्रदर्शनी 21
- वृहद स्तर पर लॉन्च की गई 'उड़ान योजना' 22
- सुशासन सूचकांक, 2021 में राजस्थान 22
- प्रदेश के 5 प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण 23
- आशा पाराशर के कथा संग्रह 'आदमखोर'का विमोचन 24
- नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में राजस्थान 24
- शरद महोत्सव-2021 25
- मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस विज़न-2030 पुस्तक का विमोचन किया 25
- राणा प्रताप सागर पन विद्युतगृह 25

नोट :

राजस्थान

बीकानेर के नोखा व चूरु के मालासर में लगेंगे बायोमॉस पॉवर प्लांट

चर्चा में क्यों?

- 30 नवंबर, 2021 को राजस्थान राज्य उर्जा विकास निगम की वार्षिक साधारण सभा में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में चूरु ज़िले के मालासर व बीकानेर ज़िले के नोखा में एक-एक नए बायोमॉस पॉवर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- ज्ञातव्य है कि इससे पहले अक्टूबर माह में ही जयपुर के फागी व बीकानेर के छतरपुर में एक-एक बायोमॉस पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की स्वीकृति दी गई है।
- एसीएस एनर्जी डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राज्य में समग्र विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिये प्रतिमाह एनर्जी एफिसिएंसी कमिटी की बैठक में समीक्षा की जाएगी, वहीं कोऑर्डिनेशन रिव्यू कमिटी को सक्रिय व कारगर बनाया जाएगा।
- राज्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने और सस्ती दर पर विद्युत की उपलब्धता तय करने के लिये दीर्घकालीन कार्ययोजना को अंतिम रुप दिया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले माह ही आयोजित ऊर्जा विकास निगम की संचालक मंडल की बैठक में राज्य के चार विंड प्लांटों से 2 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद तय की जा चुकी है।

'बैक टू वर्क' योजना

चर्चा में क्यों?

- 30 नवंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिये राज्य सरकार की 'बैक टू वर्क' योजना को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार 'बैक टू वर्क' योजना लेकर आई है।
- इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हज़ार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, जो महिलाएँ कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोज़गार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षित श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे।

- ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर निजी क्षेत्र में रोज़गार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड लक्षित श्रेणी की महिलाओं को री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिसका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मॉनिटरिंग कमिटी का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान 'बैक टू वर्क' योजना शुरू करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

चर्चा में क्यों ?

- 1 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पैनल्ड अस्पतालों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप चिरंजीवी मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी करने तथा उनकी सेवाएँ 31 मार्च, 2022 तक लिये जाने को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी मित्रों को उनके कार्यों में संचार माध्यम की आवश्यकता को देखते हुए मोबाइल चार्ज के रूप में प्रतिमाह 500 रुपए दिये जाने का भी निर्णय लिया है।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत एम्पैनल्ड निजी चिकित्सालयों में रोगियों एवं उनके परिजनों की सहायता के लिये हेल्प डेस्क स्थापित हैं। इन हेल्प डेस्क में कोविड सहायकों की सेवाएँ चिरंजीवी मित्र के रूप में ली जा रही हैं।
- चिरंजीवी मित्र एम्पैनल्ड अस्पतालों में योजना की जानकारी एवं मार्गदर्शन देने के साथ ही अस्पताल में उपचार से संबंधित आवश्यक पैकेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य संबद्ध अस्पताल के लिये रेफर कराने में रोगियों एवं उनके परिजनों की सहायता करते हैं।
- मई 2021 तक इस योजना से प्रदेश में 340 निजी अस्पताल पंजीकृत थे। अब यह संख्या बढ़कर 534 हो गई है।
- भविष्य में भी इस योजना से जुड़ने वाले निजी चिकित्सालयों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्धारित मापदंडों के अनुरूप 100 बेड से कम वाले अस्पतालों में एक तथा इससे बड़े अस्पतालों में दो कोविड सहायकों की सेवाएँ चिरंजीवी मित्र के रूप में 31 मार्च, 2022 तक लिये जाने को सहमति दी है।

इन्वेस्ट राजस्थान-2022

चर्चा में क्यों ?

- 1 दिसंबर, 2021 को आगामी जनवरी में प्रस्तावित (राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित) इन्वेस्टर्स समिट 'इन्वेस्ट राजस्थान-2022' का प्रथम स्थानीय रोड शो दिल्ली में आयोजित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम स्थानीय रोड शो में राजस्थान सरकार 68,698 करोड़ रुपए के सहमति-पत्र (एमओयू) तथा 10,099 करोड़ रुपए के आशय-पत्र (एलओआई) हस्ताक्षरित करवाने में सफल रही।
- यह निवेश राज्य के घीलोठ, भिवाड़ी, नीमराना, जयपुर, उदयपुर, अलवर एवं कई अन्य ज़िलों में स्थापित इकाइयों में प्रस्तावित है। यहाँ रीको द्वारा गत वर्षों में स्पेशल सेक्टोरल ज़ोन विकसित किये गए हैं।
- इस अवसर पर कुछ अग्रणी निवेश समूहों ने प्रदेश में बृहद् परियोजनाएँ स्थापित करने की मंशा जताई है, जैसे कि रिन्यूएबल पावर ने राज्य के विभिन्न ज़िलों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश अक्षय ऊर्जा एवं सोलर मॉड्यूल विनिर्माण हेतु प्रस्तावित किया है, जे. के. लक्ष्मी ने नागौर, उदयपुर एवं अलवर में 4250 करोड़ रुपए का निवेश सीमेंट उत्पादन तथा लाइम स्टोन उत्खनन में प्रस्तावित किया है।

- वहीं लेन्सकार्ट ने भिवाड़ी में 400 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है; डाइकिन एयरकंडिशनिंग ने 294 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव, ओकाया ईवी ने 121.36 करोड़ रुपए के निवेश से नीमराना में इलेक्ट्रिक टू-थ्री व्हीलर के उत्पादन एवं एसेंबलिंग इकाई प्रस्तावित की है।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार ने नीति नियामक तंत्र का सृजन कर औद्योगिक विकास को गति दी है। रिप्स-2019 प्रोत्साहन योजना, एमएसएमई अधिनियम, एकल खिड़की योजना (सिंगल विंडो सिस्टम) एवं वन स्टॉप शॉप (ओएसएस) हमारी वह पहल हैं, जिन्होंने निवेश की प्रक्रिया को सहज व सरल बनाया है।
- इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो एक तरह से अनूठा आयोजन है, क्योंकि यह कोरोना महामारी के बाद प्रथम ऐसा आयोजन है, जिसमें इन्वेस्ट राजस्थान-2022 से पहले विभिन्न ज़िलों एवं राज्यों में 28 और रोड शो आयोजित किये जा रहे हैं।
- गौरतलब है कि पहली बार राज्य सरकार ने न केवल एमओयू/एलओआई पर हस्ताक्षर करने पर बल दिया है, बल्कि निवेशकों की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर भी ज़ोर दिया है। ज़िला कलेक्टर पहली बार एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरह, प्रत्येक विभाग उनके नियत दिवस पर अपने-अपने विभाग से संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे।

डॉ. शिवसिंह राठौड़ बने आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष

चर्चा में क्यों?

- 2 दिसंबर, 2021 को डॉ. शिवसिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. शिवसिंह राठौड़ अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन करने वाले सबसे युवा व्यक्ति हैं। 30 जनवरी, 2016 को सदस्य के पद पर नियुक्त डॉ. राठौड़ आयोग के सबसे युवा सदस्य भी रहे।
- इस अवसर पर डॉ. शिवसिंह राठौड़ ने कहा कि अभ्यर्थियों से सीधा संवाद कायम हो सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। जिन परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है, उनका परिणाम जारी करने, लंबित वादों के निस्तारण के लिये प्रभावी प्रयास उनके द्वारा किये जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की अपेक्षानुसार भर्ती परीक्षाओं, परिणामों व अभिस्तावना भिजवाने संबंधी कार्यों को समयबद्ध रूप से संपन्न करना उनकी प्राथमिकता होगी। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने के प्रयास उनकी ओर से किये जाएंगे।
- मूलत: जोधपुर के रहने वाले डॉ. शिवसिंह राठौड़, भूगर्भशास्त्र में अधिस्नातक (गोल्ड मेडलिस्ट) व हाइड्रोजियो टूरिज्म विषय में पीएचडी हैं। इनकी विशेषज्ञता पर्यावरण एवं भूगर्भ, जल संरक्षण एवं क्षेत्रीय विकास संबंधी क्षेत्रों में भी है। आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी विभिन्न शोध-पत्र तथा जियो पार्क के निर्माण संबंधी विभिन्न आलेख डॉ. राठौड़ के द्वारा प्रकाशित किये गए हैं।
- आयोग में अपनी नियुक्ति के बाद से डॉ राठौड़ ने विभिन्न नवाचारों को बढ़ावा देने व परीक्षा प्रणाली के संवर्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रणाली की सराहना देश के विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों द्वारा भी की गई।

दिव्यांगजन दिवस पर पोस्टर का विमोचन

चर्चा में क्यों?

- 3 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने अक्षिता और अनीषा से मुलाकात की, जिन्हें हाल ही में एसएमएस अस्पताल में कोकलियर इंप्लांट हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री ने पोस्टर विमोचन के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ही कोकलियर इंप्लांट नि:शुल्क प्रोग्राम राजस्थान में प्रारंभ हुआ, जिससे प्रदेश में कई बच्चे लाभान्वित हुए हैं।
- स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब तक एसएमएस अस्पताल में 660 कोकलियर इंप्लांट हो चुके हैं और राजस्थान का मॉडल प्रोग्राम पूरे देश के लिये एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अलावा जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुरिया अस्पताल में भी यह सुविधा अब चालू कर दी गई है।

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शिमला में बैठक आयोजित

चर्चा में क्यों?

- 3 दिसंबर, 2021 को आयोजना विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने उत्तर भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तथा भारत सरकार के मध्य आपसी मुद्दों के समाधान के लिये उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की शिमला में आयोजित बैठक में राजस्थान के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राज्यों के मध्य विवादों का समाधान आपसी समन्वय, बातचीत एवं सामयिक कार्यवाही द्वारा प्रभावी तरीके से किया जा सकता है।
- इस बैठक में राज्यों के मध्य जल विवाद, टिड्डी दल आक्रमण, पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण, रेलवे प्रोजेक्ट्स, साइबर क्राईम, नए परिवहन मार्गों जैसे 47 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
- राजस्थान के विभिन्न राज्यों से लंबे समय से लंबित कई मुद्दों की प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा प्रभावी तरीके से पैरवी कर समाधान किया गया। बैठक में राज्य से संबंधित लगभग 28 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। परिषद की अगली बैठक भारत सरकार के गृह मंत्री के साथ की जाएगी।
- इस बैठक में 4 उत्तर भारतीय राज्यों व 4 केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिव एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रति वर्ष आयोजित होने वाली इस बैठक की मेज़बानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने की।

जिनोम सीक्वेंसिंग से ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि

चर्चा में क्यों?

- 5 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार की जिनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में 9 व्यक्ति कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित पाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि विभाग ने दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार को पूर्व में ही आरयूएचएस में भर्ती करवा दिया था। उनके संपर्क में आए 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए हैं, इन्हे भी आरयूएचएस में एडमिट किया जा रहा है।
- सचिव ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के सैंपल लिये गए थे, जिनमें से 9 लोग कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी 25 लोग निगेटिव हैं।
- इस दक्षिण अफ्रीकी परिवार के संपर्क में सीकर ज़िले के अजीतगढ़ का एक परिवार भी आया था। विभाग ने सीकर में उन सभी 8 लोगों की भी ट्रेसिंग की। वे सभी निगेटिव पाए गए हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में खोजे गए कोविड-19 के B.1.1.1.529 स्ट्रेन की 'वैरिएंट्स ऑफ कंसर्न' (Variants of Concern- VOC) के रूप में पहचान की है।
- इस वायरस का सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पता चला था और इसके नाम को परिवर्तित करके ओमिक्रॉन (Omicron) कर दिया गया।
- ओमिक्रॉन को विश्व स्तर पर प्रमुख डेल्टा प्लस और इसके कमज़ोर प्रतिद्वंद्वियों अल्फा, बीटा एवं गामा के साथ-साथ कोविड-19 वैरिएंट की सबसे अधिक चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है।
- हालाँकि इस बात का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है कि पिछले वायरस स्ट्रेन की तुलना में यह ओमिक्रॉन वैरिएंट कितना अधिक संक्रामक है।
- दक्षिण अफ्रीका के अलावा, इज़रायल में मलावी, बोत्सवाना, बेल्जियम और हॉन्गकॉन्ग से आने वाले लोगों में ओमिक्रॉन वैरिएंट की पहचान की गई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने उन देशों (जहाँ पहली बार उनकी पहचान की गई) के स्थान पर ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर वैरिएंट का नाम देने का पैसला किया है।
- डब्ल्यूएचओ ने Mu और Omicron के बीच दो अक्षरों Nu या Xi के बजाय ओमिक्रॉन नाम का चयन किया।

ओपन थिएटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 4 दिसंबर, 2021 को राजस्थान खेल मंत्री अशोक चांदना ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के ओपन थिएटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रो. अमेरिका सिंह ने विश्वविद्यालय के ओपन थिएटर एवं इस पर होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रकार के ओपन थिएटर भारत के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में ही स्थित हैं।
- यहाँ पर विश्वविद्यालय के कला, संगीत एवं सांस्कृतिक के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- गौरतलब है कि 26 नवंबर, 2020 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसी विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया और 26 नवंबर, 2021 को संविधान दिवस पर इस पार्क का लोकार्पण किया।

राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- 6 दिसंबर, 2021 को प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग आलोक गुप्ता एवं आयुक्त संदेश नायक ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों के लिये द्वितीय राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग 2021 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- सचिव आलोक गुप्ता एवं आयुक्त संदेश नायक ने टॉस उछालकर खेल का शुभारंभ किया।
- मुख्य आयोजनकर्त्ता ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस क्रिकेट लीग में राज्य के विभिन्न ज़िलों से 16 टीमें और 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- पहला मैच 2 k 18 Royals और आईटी स्टाईकर्स फोर्स टीमों के मध्य और दूसरा मैच सीएडी जैगुआर और 2 आईटीसी नाइट्स के मध्य खेला गया।

नागरिक सुरक्षा का 59वाँ स्थापना दिवस मनाया गया

चर्चा में क्यों ?

- 6 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा निदेशालय नागरिक सुरक्षा भवन में नागरिक सुरक्षा का 59वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा झंडारोहण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा नागरिक सुरक्षा विभाग के उप नियंत्रक इंद्रमल को राष्ट्रपति का विशिष्ठ सेवा पदक, डिवीजनल वार्डन भवानी शंकर शर्मा को राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक एवं उप नियंत्रक, रामदीनाराम जाट, श्यामसुंदर राठी, शिवराज वैष्णव, जयपाल शर्मा, महेंद्र सिंह करणावत, रामेश्वर दयाल यादव व महानिदेशक अग्निशमन अंजना गहलोत को नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के डीजीसीडी डिस्क व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- इसके साथ ही विभाग के 25 अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों को सराहनीय कार्यों के लिये आयुक्त नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशंसा-पत्र प्रदान किये गए।
- समारोह में आपदा प्रबंधन का जीवंत प्रदर्शन किया गया, जिसमें बम विस्फोट या अन्य किसी आपदा/विपदा के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों के भूतल, स्मॉक रूम, इत्यादि से हताहतों को नागरिक सुरक्षा बचाव दलों की मदद से अलग-अलग बचाव विधियों से निकालना दर्शाया गया। साथ ही आग लगने पर अग्निशमन दलों द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले अलग-अलग नॉजलों के उपयोग कर भीषण आग पर नियंत्रण करना बताया गया।

बच्चों में हाइजीन व स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु टाबर सोसायटी के साथ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

- 6 दिसंबर, 2021 को राजस्थान शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. भँवरलाल व रेकिट बेनकाइजर प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि संस्था अतरू टाबर सोसायटी के प्रतिनिधि रमेश पालीवाल द्वारा स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत एमओयू साइन किया।

प्रमुख बिंदु

- टाबर व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू होने जा रहा यह एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम है जो पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों द्वारा कोविड-19 व अन्य बीमारियों से बच्चों को बचाने व समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में मील का पत्थर साबित होगा।
- शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने टाबर सोसाइटी और शिक्षा विभाग के बीच हुए एमओयू के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण में यह कार्यक्रम टाबर सोसाइटी द्वारा 5 करोड़ 50 लाख की लागत से 2400 राजकीय विद्यालयों में चलाया जाएगा जहाँ बच्चों को खेल व अन्य रोचक गतिविधियों के माध्यम से सफाई का महत्त्व समझाया जाएगा साथ ही शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
- शैक्षणिक व सहशैक्षणिक गतिविधियों द्वारा बच्चों को स्वच्छता का अभ्यास करवाया जाएगा तथा स्वच्छता की कमी से होने वाले रोगों के प्रति बच्चों में जागरूकता लाई जाएगी।
- स्वच्छ माहौल से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी तथा स्वच्छता की कमी से विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त होकर ड्रॉपआउट होने वाले बच्चों की संख्या में भी इस कार्यक्रम से कमी आएगी।

अत्यावश्यक सेवाओं की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं के साथ जुड़े समस्त कार्यालय एवं कर्मचारीयों तथा उनके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को 6 दिसंबर, 2021 से आगामी 6 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी आदेशानुसार उक्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
- इसे मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत तुरंत प्रभाव से 108 आपातकालीन सेवाओं के साथ-साथ 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाएँ जिनका संचालन प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एंबुलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया है।

एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक

चर्चा में क्यों ?

- 7 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एनर्जी) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने विद्युत भवन में आयोजित एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा 2026-27 तक बिजली की वर्षवार बिजली उपलब्धता, मांग और आपूर्ति व्यवस्था का रोडमेप बनाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त सचिव एनर्जी आलोक रंजन के नेतृत्व में प्लानिंग व कोआर्डिनेशन सेल का गठन भी किया गया है यह सेल राज्य की सभी विद्युत कंपनियों से परस्पर समन्वय व संवाद कायम करेगा, ताकि सूचनाओं की त्वरित प्राप्ति के साथ ही समयबद्ध कार्यनिष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।
- एसीएस माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी सचिव ने बताया कि ऊर्जा विकास निगम के निदेशक पावर ट्रेडिंग पीएस सक्सेना आठ से दस दिनों में विद्युत उत्पादन निगम, तीनों डिस्कॉम, अक्षय ऊर्जा निगम व ऊर्जा विकास निगम सहित संबंधित संस्थाओं के विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ मिलकर रोडमेप की रूपरेखा तैयार करेंगे।
- यह दल राज्य में विद्युत उत्पादन के कन्वेशनल सोर्सेज के साथ ही अक्षय ऊर्जा व नवीकरण सोर्सेज से सोलर, विंड और बायोमास आदि की उपलब्ध क्षमता व भावी संभावनाओं का भी रोडमेप में समावेश करेगा। बाद में इसे अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- वर्ष 2019-20 में राज्य में 6000 मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाने की घोषणा की गई थी, जिसे चरणबद्ध तरीके से इस रोडमेप के आधार पर बढ़ाया जाएगा। इस तरह सभी जिलों में काश्तकारों को खेती के लिये दिन में बिजली उपलब्ध कराने की बजट घोषणा का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी कमेटी की पहली बैठक जून 2019 में हुई थी। जुलाई 2021 में भी आयोजित बैठक में तात्कालीक समाधान पर चर्चा की गई। दिसंबर 2021 के अंत तक विभाग स्तर पर कार्ययोजना को अंतिम रूप दे रूप दे दिया जाएगा।

नोट :

‘राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक’पुस्तक का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बीकानेर ज़िले में ‘राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और विजय सिंह पथिक’पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की इस कड़ी में राजस्थान राज्य अभिलेखागार परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ. कल्ला ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में विजय सिंह पथिक की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण रही। उनके समग्र व्यक्तित्व से संबंधित मूल दस्तावेज़ों पर आधारित यह पुस्तक भावी पीढ़ी के लिये फायदेमंद साबित होगी।
- पुस्तक के संपादक तथा राजस्थान राज्य अभिलेखागार निदेशक डॉ. महेंद्र खड़गावत ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1982 में ओरल हिस्ट्री परियोजना के तहत उस दौर के जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के संस्मरणों को ध्वनिबद्ध करने का कार्य दिया गया था, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है।
- राजस्थान और आसपास के राज्यों द्वारा विजय सिंह पथिक के मूल अभिलेखों पर आधारित पुस्तक की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके मद्देनज़र अभिलेखागार द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है।
- कला-संस्कृति मंत्री ने राजस्थानी भाषा को विश्व की समृद्धतम भाषाओं में से एक बताया तथा कहा कि इसमें प्रचुर साहित्य विद्यमान है। तथा दुनिया भर में दस करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते और समझते हैं।
- राजस्थान की विधानसभा द्वारा इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने का प्रस्ताव वर्षों पूर्व पारित करवाया जा चुका है। उन्होंने राजस्थानी फिल्मों के प्रोत्साहन के लिये राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
- इस अवसर पर डॉ. कल्ला ने अभिलेखागार और म्यूजियम का अवलोकन किया। डिजिटल अभिलेखागार, अभिलेख संग्रहालय तथा अभिलेख प्रबंधन की सराहना की। बही और पट्टा रजिस्टर का अवलोकन किया तथा पट्टा जारी करने की जानकारी भी ली।
- डिजिटाइज़ेशन कार्य को भविष्य के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण बताया। अभिलेखागार की दीर्घाओं में शिवाजी महाराज दीर्घा, महाराणा प्रताप दीर्घा, टेस्सीतोरी दीर्घा आदि का अवलोकन किया।

इन्वेस्ट राजस्थान-2022 मुंबई एवं अहमदाबाद में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम

चर्चा में क्यों ?

- 8 दिसंबर, 2021 को इन्वेस्ट राजस्थान-2022 समिट की इस कड़ी में मुंबई एवं अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में क्रमशः 1 लाख 94 हज़ार 800 करोड़ रुपए तथा 1 लाख 5 हज़ार 700 करोड़ रुपए के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) और एलओआई (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- अक्षय ऊर्जा, खान और खनिज, सिटी गैस, फार्मा, इंजीनियरिंग सहित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 1 लाख 27 हज़ार 459 करोड़ रुपए के एमओयू और 67 हज़ार 379 करोड़ रुपए से अधिक के एलओआई शामिल हैं, जिससे भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख 44 हज़ार रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
- जेएसडब्ल्यू फ्यूचर एनर्जी ने जैसलमेर ज़िले में 10 हज़ार मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिये 40 हज़ार करोड़ रुपए का प्रस्ताव, वेदांता समूह ने 33 हज़ार 350 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्लोरेशन एक्सपेंशन का प्रस्ताव तैयार किया है तथा ग्रीनको एनर्जीज ने 30 हज़ार करोड़ रुपए की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना का ऑफर दिया है।

नोट :

- अडानी ग्रीन एनर्जी ने जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में 4 हज़ार मेगावाट की 20 हज़ार करोड़ रुपए की अक्षय ऊर्जा परियोजना का प्रस्ताव दिया है। अडानी टोटल गैस ने उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में सिटी गैस सप्लाई की 3 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव रखा है।
- अन्य 40 प्रस्तावित परियोजनाओं में कृष फार्मा ने 750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सिरोही में एक फार्मा निर्माण इकाई का प्रस्ताव रखा है।
- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने मेगा इन्वेस्टमेंट समिट इन्वेस्ट राजस्थान-2022 को बढ़ावा देने के लिये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाकर औपचारिक आगाज़ किया।
- निवेशकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ओएसएस (वन स्टॉप शॉप) सिस्टम स्थापित करके एक बहुत ही अनूठी पहल की है। कोई भी निवेशक जो राज्य में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करना चाहता है, वह आसानी से आवेदन कर सकता है और व्यवसाय शुरू कर सकता है। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश हेतु कस्टमाइज्ड पैकेज भी दिया जाता है।
- इस कड़ी में अहमदाबाद में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम में 1 लाख 5 हज़ार 700 करोड़ रुपए के एमओयू (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) और एलओआइ (लेटर ऑफ इंटेंट) पर हस्ताक्षर किये गए। खनिज, टेक्सटाइल, एसटीपी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, पेट्रो-केमिकल्स, बॉयो-डीज़ल, सोलर, पर्यटन और हैंडीक्रॉफ्ट सहित अन्य क्षेत्रों में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में 41 हज़ार 590 करोड़ रुपए के 12 एमओयू और 64 हज़ार 110 करोड़ रुपए से अधिक के 28 एलओआई शामिल हैं, जिससे भविष्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होने की संभावना है।
- अज़ूर पावर ने फतेहगढ़, जैसलमेर में 24 हज़ार करोड़ रुपए का सोलर पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव, सोलरपैक कॉर्पोरेशन ने फलौदी, जोधपुर में 1 हज़ार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना का प्रस्ताव, एसीएमई क्लीनटेक ने जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में 8 हज़ार 200 करोड़ रुपए की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- टोरेंट गैस ने अलवर शहर में 5000 करोड़ रुपए की गैस आपूर्ति परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एनयू विस्टा ने चित्तौड़ और नागौर में हज़ार करोड़ रुपए के निवेश पर दो सीमेंट निर्माण संयंत्र प्रस्तावित किये हैं।
- अहमदाबाद के होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आयोजित कार्यक्रम में करीब 15 नए निवेशकों से वन-टू-वन मीटिंग की गई। साथ ही, उद्योग जगत् से जुड़े लोगों को राज्य में 24-25 जनवरी को आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान के लिये भी आमंत्रित किया गया।

चिकित्सा मंत्री ने कैंसर प्रिवेंटिव एंड अर्ली डिटेक्शन मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

- 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपने राजकीय आवास से कैंसर प्रिवेंटिव एंड अर्ली डिटेक्शन मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के सीएसआर फंड के सहयोग से 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत की मोबाइल वैन प्रशासन गाँवों के संग अभियान के दौरान गाँव-गाँव जाकर कैंसर की जाँच करेगी।
- ज़रूरतमंद एवं गरीब लोग जो सामान्यत: अस्पताल नहीं आ सकते हैं, कैंसर प्रीवेंटिव मोबाइल वैन उनके लिये बेहद कारगर साबित होगी।
- कैंसर प्रिवेंटिव मोबाइल वैन के ज़रिये शुरुआती स्टेज में कैंसर की पहचान की जा सकेगी। इस वैन में मुख्य रूप से स्तन कैंसर, बच्चादानी का कैंसर, मुँह का कैंसर और फेंफड़ों के कैंसर की नि:शुल्क जाँच की जाएगी।
- वैन में डिजिटल मेमोग्राफी स्तन कैंसर के लिये, डिजिटल कालपोस्कॉपी बच्चादानी कैंसर के लिये, डिजिटल चेस्ट एक्स-रे फैफड़ों के कैंसर के लिये, इंडोस्कॉपी जाँच मुँह के कैंसर के लिये और तुरंत निदान एवं अन्य डिस्कशन हेतु टेलीमेडिसन की भी सुविधा होगी।

नोट :

सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योज़ना-2021

चर्चा में क्यों ?

- 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योज़ना-2021 के तहत प्रदेश में पात्र अलाभकारी संस्थाओं को विकास शुल्क एवं बीएसयूपी (बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पूअर) शेल्टर फंड राशि से भी मुक्त रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् मान्यताप्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना-2021 लागू की है।
- इस योजना के तहत बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिक्षावृत्ति तथा नशा करने वाले व्यक्तियों, निर्धन, बेघर, ट्रांसजेंडर एवं वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में मान्यताप्राप्त अलाभकारी संस्थाओं को विभिन्न सुविधाएँ, रियायत एवं छूट प्रदान की जा रही हैं।
- इसके तहत इन संस्थाओं को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ नियमन के लिये निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देय है। साथ ही उनके द्वारा क्रय की गई अथवा लीज़ पर ली गई अचल संपत्ति के दस्तावेज़ों पर पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी में भी शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।
- मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविरों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में जनोपयोगी सुविधाएँ जैसे- चकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएँ, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ आश्रम, धर्मशाला, दिव्यांगजन केंद्र, नशामुक्ति केंद्र, कन्या आश्रम, बाल गृह आदि के विकास को गति दी जा सके।

राजस्थान पर्यटन एवं वेडिंग डेस्टिनेशन में सर्वश्रेष्ठ

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन पत्रिका ट्रैवल एंड लीज़र मैग्ज़ीन के रीडर्स सर्वे में राजस्थान को एक साथ दो अवार्ड से नवाज़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- 'इंडियाज बेस्ट अवार्ड' के 10वें संस्करण में विभिन्न श्रेणियों में पाठकों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर ट्रैवल एंड लीज़र इंडियाज बेस्ट अवाड्‌र्स-2021 में राजस्थान पर्यटन को 'सर्वश्रेष्ठ राज्य' और 'सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टिनेशन' पुरस्कार से नवाज़ा गया है।
- मैग्ज़ीन के सर्वे में राजस्थान को पूरे देश में शाही शादियों के लिये बेस्ट वेडिंग डेस्टीनेशन अवार्ड मिला है। इसके साथ ही राजस्थान आने वाले पर्यटकों के बहुआयामी पर्यटन के लिये पूरे देश में बेस्ट स्टेट का अवार्ड भी मिला है।
- ट्रैवल एंड लीज़र मैग्ज़ीन ने पर्यटन की ओवरऑल कैटेरी में राजस्थान को पूरे देश में बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया है।
- राजा-महाराजाओं की जन्मस्थली और किले-हवेलियों की विरासत को सँजोए मरुधरा की भूमि राजस्थान आज भी खूबसूरती के मामले में सबसे आगे है। खासतौर पर स्टेटस सिंबल बन रही डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जैसी कई जगहें हैं, जहाँ राजस्थान कई सेलिब्रिटीज और कई कपल के लिये गवाह बनता है। इसी को लेकर राजस्थान पर्यटन को यह सफलता हासिल हुई है।
- राजस्थान समृद्ध और रंगीन विरासत की भूमि है, जो सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। बुनियादी ढाँचे और आधुनिक आतिथ्य में हाल के विकास ने इसे विश्व के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाने में योगदान दिया है।
- राजस्थान को यह मान्यता दिलाने में उदयपुर की अहम भूमिका है। उदयपुर अपने अनोखे स्तर के आकर्षण के साथ अपने सिटी पैलेस; बापू बाज़ार; जग मंदिर; लेक पैलेस होटल और अन्य कई शानदार एवं अनोखे रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन; चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ महोत्सव के साथ राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ विवाह स्थल के रूप में वर्गीकरण में विशेष उल्लेख प्राप्त करता है।

- यह पुरस्कार मिलने से राजस्थान की होटल इंडस्ट्री और पर्यटन जगत् के विकास का प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस सर्वे के आधार पर ही विश्वभर में पर्यटन उद्योग यह टॉप डेस्टिनेशन तय करता है। यहाँ पर अमेरिका, यूरोप सहित विश्वभर से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इज़ाफा होगा।

अलवर में शुरू हुआ प्रदेश का पहला नि:शुल्क टेली मेडिसिन और आत्मविश्वास केंद्र

चर्चा में क्यों?

- 10 दिसंबर, 2021 को राज्य के सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर ज़िले में नेक कमाई समूह की ओर से अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से संचालित प्रदेश के पहले गैर-सरकारी नि:शुल्क टेली मेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर ज़िला मुख्यालय पर यह नवाचार किया जा रहा है। यहाँ सामाजिक कल्याण विभाग की सभी योजनाएँ संचालित होंगी और यह प्रयोग सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में जन-सहभागिता से लागू किया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि अलवर ज़िले में सामाजिक कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ हर गरीब और ज़रूरतमंद को मिले, इसके लिये स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इसके लिये अलवर ज़िले के हर ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।
- एनईबी हाउसिंग बोर्ड में कुंती अग्रवाल के निर्देशन में संचालित आत्मविश्वास केंद्र में टेली-मेडिसिन सेंटर में मंत्री जूली ने समाज सेवा के लिये कुंती अग्रवाल, बबली शर्मा और डॉ. कुमुद गुप्ता को सम्मानित किया।
- इसी प्रकार दाउदपुर में गुरु नानक कॉलोनी स्थित आत्मविश्वास केंद्र पर समाज सेवी गुरुप्रीत सिंह, सोनम कौर एवं संचालिका जगमीत कौर का सम्मान किया गया।
- आत्मविश्वास केंद्रों में डॉ. गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से महिलाओं के लिये सेनेटरी नैपकीन सहित वस्त्र व गर्म कपड़े प्रदान किये जाएंगे।

जयपुर डिस्कॉम का रोड शो

चर्चा में क्यों?

- 11 दिसंबर, 2021 को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये जयपुर डिस्कॉम द्वारा एक रोड शो का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को जयपुर डिस्कॉम के एमडी नवीन अरोड़ा ने जवाहर सर्किल से फ्लैग दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी, भारत सरकार द्वारा 8 दिसंबर से 14 दिसंबर, 2021 तक ऊर्जा संरक्षण जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में नोडल एजेंसी जयपुर डिस्कॉम द्वारा इस रोड शो का आयोजन किया गया।
- जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने बताया की इस रोड शो में करीब 30 दोपहिया व चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हुए। अरोड़ा ने कहा कि पेट्रोल व डीज़ल के वाहनों से बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु ग्रीन ट्रांसपोर्ट को अपनाएँ।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सोलर पालिसी एवं विंड व हाईब्रिड पालिसी-2019 में कई दूसरे प्रावधान दिये गए हैं।
- राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन हेतु अलग श्रेणी निर्धारित की गई है, जिसमें कम दर पर चार्जिंग का प्रावधान किया गया है।
- उन्होंने कहा कि इस आयोजन से आमजन में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी एवं प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा भी मिलेगा तथा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

नोट :

ई-वर्क एवं ई-मैप मोबाईल ऐप

चर्चा में क्यों ?

- 13 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीणा ने इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में एन.आई.सी. एवं जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा बी.एम.ज़ेड. के सहयोग से निर्मित ई-वर्क एवं ई-मैप मोबाईल ऐप का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि ई-वर्क एवं ई-मैप मोबाईल ऐप के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी राज्यस्तरीय योजनाओं की मॉनिटरिंग एक ही पोर्टल पर हो सकेगी।
- उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के अंतर्गत प्रदेश के 33 ज़िले, 352 पंचायत समिति, 11 हज़ार 326 ग्राम पंचायतें एवं 46 हज़ार 118 गाँवों में 25 से अधिक योजनाएँ संचालित हैं। इन योजनाओं पर 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बजट का प्रावधान है।
- राज्यस्तरीय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 10 लाख से अधिक कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐप की सहायता से राज्यस्तरीय योजनाओं में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- ग्रामीण विकास की कार्य योजना बनाने से उसके पूर्ण होने के उपरांत एसेट रजिस्टर संधारण तक के समस्त कार्यों का एकल प्लेटफॉर्म द्वारा संपादन किया जा सकेगा। ई-वर्क एवं ई-मोबाइल ऐप का उपयोग ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शासन स्तर तक के समस्त अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- विभाग द्वारा आमजन को सूचित करने के लिये सूचनाओं को पब्लिक डॉमेन में रखे जाने का प्रावधान किया जा रहा है। ई-वर्क एवं ई-मैप ऐप को जन सूचना पोर्टल से इंटीग्रेशन किया जाएगा।
- इस ऐप एवं पोर्टल का विकास दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण का रोल-आउट किया जा चुका है एवं द्वितीय चरण को अप्रैल 2022 तक लागू किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना, स्व-विवेक ज़िला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ज़िला नवाचार निधि योजना, श्री योजना एवं स्मार्ट विलेज सहित 11 राज्यस्तरीय योजनाएँ संचालित हैं।

पाँच दिवसीय राष्ट्रीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 13 दिसंबर, 2021 को राज्य के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में आयोजित पाँच दिवसीय राष्ट्रीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा नाट्यशास्त्र कार्यशाला पर प्रकाशित विशेषांक 'संस्कृत सेतु'का लोकार्पण किया गया।
- ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर आयोजित हो रही इस राष्ट्रीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता कर रहे विश्वविख्यात संस्कृत एवं नाट्य मनीषी प्रोफेसर राधावल्लभ त्रिपाठी ने कहा कि नाट्यशास्त्र पर केंद्रित पाँच दिन की कार्यशाला प्रदेश में अपने ढंग का पहला आयोजन है।
- उन्होंने कहा कि नाट्यशास्त्र भारत की अनमोल विरासत है। ढाई हज़ार साल पहले संस्कृत में रचा गया यह ग्रंथ भारतीय कलाओं का विश्वकोश है तथा साहित्यशास्त्र, सौन्दर्यशास्त्र और नाट्यचिंतन का भी मूलाधार है।

नोट :

- इस कार्यशाला के माध्यम से युवा रंगकर्मी भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र का प्रामाणिक परिचय प्राप्त करके अपने प्रयोगों को अपने देश की कलापरंपरा में डाल सकेंगे। भारत के राष्ट्रीय रंगमंच की खोज में भी यह कार्यशाला एक पड़ाव बनेगी।
- कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव, गायत्री राठौड़ ने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यशाला नाट्य प्रेमियों, रंग कर्मियों, शोधार्थियों में एक नए उत्साह का संचार करेगी और कालांतर में यह एक मील का पत्थर साबित होगी।
- प्रख्यात फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी रघुवीर यादव ने कहा कि यह कार्यशाला नाट्यशास्त्र की बारीकियों को समझने का एक बड़ा अवसर है। नाट्यशास्त्र में निहित रस, भाव और भनिति भंगिमाओं के प्रयोग नाट्यकारों को पूर्ण तथा परिष्कृत बनाते हैं। नाट्यशास्त्र अभिनय का अनुशासन है।

राजस्थान को मिला नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में ऊर्जा संरक्षण हेतु किये गए प्रशंसनीय कार्यों के लिये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड (द्वितीय) से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह द्वारा यह पुरस्कार राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के निदेशक (तकनीकी) नरेंद्र सिंह निरवान और अतिरिक्त आवासीय आयुक्त विमल शर्मा को दिया गया।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी एवं चेयरमैन अक्षय ऊर्जा निगम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि अन्य प्रदेशों के लिये राजस्थान की अनुकरणीय उपलब्धियों को देखते हुए स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को यह पुरस्कार दिया गया है।
- एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019, राजस्थान पवन व हाईब्रिड नीति, 2019 व राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के क्रियान्वयन से राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन गया है।
- देश के ऊर्जा क्षेत्र के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे अधिक ऊर्जा उपभोग वाले राज्यों की श्रेणी में एनर्जी एफिशिएंसी के क्षेत्र में राजस्थान के कुशल प्रबंधन को देखते हुए इसका चयन किया गया है।
- इससे पहले पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में राजस्थान को फ्रंट रनर प्रदेश के रूप में चुना जा चुका है।

ऊर्जा मंत्री ने बाँटे राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 14 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में बड़ी स्केल की चार इकाईयों सहित 23 संस्थाओं को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने श्री सीमेंट रास, जेके सीमेंट मांगरोल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी और डिविजनल हॉस्पिटल नार्थ वेस्टर्न रेलवे जोधपुर को शील्ड और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।
- ऊर्जा मंत्री ने कालीसिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन निगम झालावाड़, रामपुरा अगुचा माइंस हिंदुस्तान जिंक, फ्लक्स लाईट निमस जयपुर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज कांकरोली, श्री मोहता आयुर्वेदिक रसायनशाला बीकानेर, नार्थ वेस्टर्न रेलवे मुख्यालय भवन जयपुर, सीकर रेलवे स्टेशन, बाड़मेर रेलवे स्टेशन, मोहर सिंह फागरिया बीकानेर, रामनारायण वैष्णव जयपुर, कमल गोयल अजमेर तथा सचिव गुप्ता गोटन को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया

नोट :

- इसी तरह इंडस्ट्री जनरल लार्ज स्केल केरेज वर्कशाप अजमेर, एनर्जी क्लब एमएनआईटी जयपुर, श्री राम वीनाइल एंड केमिकल कोटा, चंबल फर्टिलाइजर गडेपान, सिरेमिक्स ग्रेनिटो बीकानेर और एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज जयपुर को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।
- इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना हो या अक्षय ऊर्जा उत्पादन या फिर ऊर्जा दक्षता हो या ऊर्जा संरक्षण, राजस्थान सभी क्षेत्रों में देश में अग्रणी प्रदेश हो गया है।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस एक साल को प्रदेश के गोल्डन वर्ष के रूप में देखा जा सकता है। इस साल 2021-22 में रिकार्ड 2200 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है।
- केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी ने राजस्थान को फ्रंट रनर राज्य घोषित किया है साथ ही ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये राज्य को पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान में अडानी, मित्तल, जेएसडब्ल्यू जैसे 16 बड़े निवेशक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 59 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू/एलओआई पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के महाप्रबंधक सुनित माथुर ने बताया कि राज्य में 2009 से ऊर्जा बचत के लिये प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किया जा रहा है।

इन्वेस्ट राजस्थान-2022:

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को इन्वेस्ट राजस्थान-2022 का आरंभ संपूर्ण प्रदेश में मैनचेस्टर के रूप से पहचान बना चुके भीलवाड़ा ज़िले से हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम द्वारा समिट में आए अतिथियों एवं उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विज़न राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना व प्रगति के नए आयाम स्थापित करना है।
- राजस्थान देश का प्रथम राज्य है जहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश का बेहतर वातावरण बनाने व रोज़गार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे, जिसकी शुरूआत भीलवाड़ा से हुई है।
- कार्यकम का केंद्रबिंदु एमओयू सेरेमनी रही, जहाँ सभी क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों के साथ भीलवाड़ा ज़िला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने एमओयू निष्पादित किये।
- समिट के दौरान राज्य सरकार की उद्योगों से जुड़ी जानकारी एवं सरकार द्वारा किये जा रहे सहयोग के प्रति उद्यमियों ने उत्साह दिखाया एवं कार्यक्रम के दौरान ही 10 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए।
- ज़िलास्तरीय समिट में 700 से अधिक उद्यमियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया, वहीं अमेरिका, दुबई, कतर, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, इंग्लैंड, जापान आदि से अप्रवासी भारतीयों के 26 संगठन ऑनलाइन जुड़े।
- लगभग 200 औद्योगिक इकाइयों एवं निवेशकों द्वारा टेक्सटाइल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, टूरिज्म, मिनरल्स एंड केमिकल्स, फर्नीचर, सीमेंट प्रोडक्ट सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में 10 हज़ार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के निवेश करने पर समझौता हुआ।
- समिट में भीलवाड़ा ज़िले के संपूर्ण उद्योग एवं वाणिज्य परिदृश्य को दर्शाती हुए टेक्सटाइल, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, मिनरल्स व माइनिंग, बैंकिंग, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइज़ेशन, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, ज़िलास्तरीय सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, वूडन व स्टोन कार्विंग की आकर्षक स्टॉल्स में उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
- समिट में अतिथियों द्वारा उद्योग से जुड़ी जानकारियों के ब्रोशर का विमोचन किया गया एवं ज़िले में उद्योग की संभावनाओं की जानकारी शार्ट फिल्म द्वारा दी गई।
- भीलवाड़ा ज़िला कलेक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने बताया कि 10 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश होने पर ज़िले में 25 हज़ार से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा।

नोट :

- समिट में यूआईटी की ओर से आज़ादनगर में प्रस्तावित मेडिसिटी योजना का प्रजेंटेशन दिया गया। इसमें सुपर स्पेशिएयलिटी हॉस्पिटल, फॉर्मा कंपनियाँ, पार्क आदि सुविधाएँ होंगी।

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 15 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में संविदा नियुक्ति के लिये नियम बनाने, चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण हेतु नीति के प्रारूप के अनुमोदन सहित कई अन्य महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिये रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति हेतु 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021' बनाए जाने का अनुमोदन किया। इस निर्णय से मैनपावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- मंत्रिमंडल ने चरागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिये प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया। चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चरागाह भूमि पर कम-से-कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार अधिकतम 100 वर्गमीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस नीति से चरागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिये राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की जॉइंट वेंचर कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाटयाडू एवं नेडान गाँव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंज़ूरी दी।
- इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये केरालियां गाँव में 64.38 हेक्टेयर राजकीय भूमि को लीज़ पर सशर्त कीमतन आवंटित करने की मंज़ूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- बैठक में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021 को मंज़ूरी दी गई। यह नीति स्थाई एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देगी।
- इस नीति के तहत लगने वाली इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को रिप्स-2019 के प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे। इससे राज्य के भूजल सुरक्षित क्षेत्रों (सेफ ब्लॉक्स) में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों, उद्यमियों एवं कामगारों के लिये लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे।
- बैठक में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम-1966 में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। इससे सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिये आवश्यक अर्हता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित किया जा सकेगा। इस निर्णय से नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आमजन के नगर नियोजन संबंधी कार्यों को सुगमता से संपादित किया जा सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के तहत जारी अधिसूचना में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन को जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के सभी विभागों एवं विकास प्राधिकरणों, यूआईटी, नगर निगम, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं आदि को शौचालय निर्माण, रखरखाव एवं संचालन का कार्य समयबद्ध तथा त्वरित रूप से किये जाने के लिये एक विकल्प उपलब्ध हो सकेगा।

नोट :

- बैठक में राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड का गठन करने की मंज़ूरी दी गई। इस संस्था के गठन से राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को लोक उपापन, अनुबंध प्रबंधन, कराधान, सेवा नियमों आदि क्षेत्रों में आवश्यक विशेषज्ञता, परामर्श एवं सहयोग मिल सकेगा।

ज्ञानदूत 2.0

चर्चा में क्यों?

- 15 दिसंबर, 2021 को राजस्थान कॉलेज शिक्षा आयुक्त शुचि त्यागी ने महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में विषयपरक ज्ञानवर्द्धन, अकादमिक समस्या समाधान एवं उनके समय का रचनात्मक सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये ज्ञानदूत कार्यक्रम का दूसरा चरण ज्ञानदूत 2.0 आरंभ करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत दिसंबर के अंतिम सप्ताह से स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित करवाई जाएंगी, जिनमें राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत् संकाय सदस्य पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर व्याख्यान देंगे।
- शुचि त्यागी ने बताया कि ज्ञानदूत के इस दूसरे चरण में फिलहाल 14 विषयों में ऑनलाइन कक्षाएँ आरंभ करवाई जाएंगी, जिनकी संख्या में विद्यार्थियों की मांग अनुसार बढ़ोतरी की जा सकती है।
- विषयवार अध्यापन व्यवस्था के लिये महाविद्यालयों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रत्येक विषय को सप्ताह में 3 दिन तथा प्रत्येक दिन 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मांग अधिक होने पर इन कक्षाओं का समय बढ़ाया जा सकेगा। इसमें कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों का समय अलग-अलग रहेगा।
- उन्होंने बताया कि पहले की तरह ये कक्षाएँ सभी राजकीय, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क होंगी। प्रत्येक रविवार को इन कक्षाओं का प्रॉब्लम सॉल्विंग विशेष सत्र आयोजित करवाया जाएगा।
- कार्यक्रम के संचालन के लिये आयुक्तालय स्तर पर नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के समन्वय में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉ. विनोद भारद्वाज को समन्वयक एवं डॉ. ललिता यादव को सह-समन्वयक नामित करते हुए 12 सदस्य और जोड़े गए हैं।
- इन कक्षाओं को दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आरंभ करवाना प्रस्तावित है। ये ऑनलाइन लाइव कक्षाएँ नियमित अध्यापन के अतिरिक्त केवल एक सहायक शिक्षण व्यवस्था है, जो नियमित कक्षाओं का प्रतिस्थापन नहीं है।
- उल्लेखनीय है कि पिछले सत्र में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यार्थियों की अध्ययन निरंतरता के लिये यह कार्यक्रम आरंभ किया गया था, जिसमें लगभग डेढ़ माह तक कक्षाओं का संचालन कर महत्त्वपूर्ण विषयपरक बिंदुओं पर अध्यापन करवाया गया।
- पहले चरण में 22 विषयों में 12 राजकीय महाविद्यालयों को केंद्र बनाकर 621 सत्र आयोजित करवाए गए, जिनके वीडियो कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञानदूत चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अभी तक 4 लाख 36 हज़ार से अधिक व्यूअर्स ने देखा है। इस कार्यक्रम में 48 हज़ार विद्यार्थी पंजीकृत हुए।

कला एवं संस्कृति मंत्री ने किया 'लोकरंग-2021' का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

- 16 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने जवाहर कला केंद्र (जेकेके) में लोक कलाकारों के उत्सव, 24वें 'लोकरंग-2021' का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस 11 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश सहित देशभर के 650 से अधिक लोक कलाकार अपने-अपने क्षेत्र की लोक कलाओं की खूबसूरती को प्रस्तुत करेंगे।

- यह समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जेकेके, कला एवं संस्कृति विभाग और रुडा (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- लोकरंग के शुभारंभ के साथ ही पहले दिन कार्यक्रम में कलाकारों ने गुजरात का गरबा रास, महाराष्ट्र का लावणी नृत्य (गणपति), गोवा का कुनबी, तमिलनाडु का डोलू कुनीथा, पश्चिम बंगाल का छऊ (महिसासुर वध), मध्य प्रदेश का बधाई-जवारा, उत्तर प्रदेश का धोबिया, बिहार का झिझिया, जोधपुर का लंगा गायन और चरी नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी।
- इसके साथ ही जेकेके के शिल्पग्राम में रुडा (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण) के सहयोग से राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की भी शुरुआत हुई। मेले का उद्घाटन कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला ने किया।
- जेकेके के शिल्पग्राम में शहनाई-नगाड़ा, तीन ढोल, कठपुतली, भरतपुर का नट, अलगोजा नृत्य, बहुरूपिया, कालबेलिया और बम रसिया की प्रस्तुति हुई।
- मेले में देशभर के पुरस्कृत शिल्पियों द्वारा निर्मित कलात्मक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। विजिटर्स के लिये यह प्रदर्शनी 16 से 26 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगी।

रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड-2021

चर्चा में क्यों?

- 16 दिसंबर, 2021 को कोंडे नास्ट ट्रैवलर की ओर से प्रतिष्ठित रीडर्स ट्रैवलर अवार्ड-2021 की घोषणा की गई, जिसमें राजस्थान राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप के खिताब से नवाजा गया। इसके अलावा 'फेवरेट लीजर डेस्टीनेशन' इन इंडिया श्रेणी में भी राजस्थान को उपविजेता घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- खूबसूरत, भव्य और गौरवशाली प्रदेश राजस्थान को सड़क यात्रा के ज़रिये देखने तथा अनुभव करने के रोमांचकारी एवं आनंददायी अहसास के लिये रोड ट्रिप हेतु पसंदीदा भारतीय राज्य चुना गया है।
- देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अपने में कई आकर्षण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। यहाँ की मेहमाननवाज़ प्रकृति यहाँ आने वाले मेहमानों को सुखद प्रवास और यात्रा का आश्वासन देती है। यही कारण है कि इसे रेटिंग में देश के पसंदीदा अवकाश गंतव्यों की श्रेणी में शुमार किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि कोंडे नास्ट ट्रैवलर नौ अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संस्करणों के साथ एक प्रमुख यात्रा पत्रिका है। इसके द्वारा ट्रैवलर रीडर्स चॉइस अवाड्र्स स्वीपस्टेक अवधि के दौरान रेटिंग जमा करने वाले लाखों उत्तरदाताओं के परिणामों के सारणीकरण के बाद घोषित किये जाते हैं।

'आपका विश्वास-हमारा प्रयास' प्रदर्शनी

चर्चा में क्यों?

- 18 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाहर कला केंद्र में 'सेवा ही धर्म-सेवा ही कर्म' के संकल्प के साथ राज्य सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित चार दिवसीय प्रदर्शनी 'आपका विश्वास-हमारा प्रयास' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों के साथ ही विभिन्न उपलब्धियों से जुड़े साहित्य तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की पत्रिका 'सुजस' के संयुक्तांक एवं राजस्थान आवासन मंडल की उपलब्धियों पर आधारित फोल्डर का विमोचन भी किया।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 21 स्टॉल्स पर जाकर उनका अवलोकन किया। विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर उन्होंने संबंधित विभाग की उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी ली।
- उन्होंने दिव्यांगों को स्कूटी की चाबी, ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर भेंट की। गृह विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र एवं पुलिस सखी से मिले और उनकी हौसला अफजाई की। जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की स्टॉल पर उन्होंने 'नागौर लिफ्ट परियोजना' के मॉडल का अवलोकन किया। वन विभाग की स्टॉल पर मुख्यमंत्री ने 'घर-घर औषधि योजना' के तहत किये जा रहे औषधीय पौधों के वितरण की जानकारी ली।
- इसी तरह मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों का डिजिटल प्रस्तुतीकरण देखा।

वृहद स्तर पर लॉन्च की गई 'उड़ान योजना'

चर्चा में क्यों?

- 19 दिसंबर, 2021 को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री निवास से 'आई एम शक्ति उड़ान योजना', 'जागृति-बैक टू वर्क योजना' तथा प्रदेश में झुंझुनू, चूरू, बूंदी एवं हनुमानगढ़ ज़िलों में नवनिर्मित 'सखी वन स्टॉप सेंटर' का लोकार्पण किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि इस योजना से राजस्थान की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके के जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा।
- इस महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य की हर किशोरी और महिला तक निशुल्क सेनेटरी नेपकिन पहुँचाया जाएगा। हर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र से किशोरियाँ अपनी सेल्फ हाइजीन के लिये इस योजना का लाभ ले पाएंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना को संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री की स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान व निरोगी राजस्थान की संकल्पना का सपना साकार करने की कड़ी में महिलाओं को स्वच्छता व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम उड़ान योजना के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इतने बड़े स्तर पर यह देश में राजस्थान की अपने आप में एक अनूठी पहल है।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान में महिलाओं के लिये स्वास्थ्य जागरूकता एवं नि:शुल्क सेनेटरी वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में वर्णित 'Health एवं Hygiene' को ध्यान में रखते हुए छात्राओं एवं किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी महिलाओं को, आवश्यकतानुसार यह सुविधा 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना' के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ घूंघट प्रथा भी है तथा महिलाएँ अपनी ऐसी समस्याएँ किसी से संकोचवश कह नहीं पाती हैं व इस कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा उन्हें समय पर इलाज भी नसीब नहीं होता। अत: महिला SHG, सामाजिक संस्थाओं एवं NGOs के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चलाकर सेनेटरी नैपकिन का वितरण करवाया जाएगा।
- इस हेतु इन संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसकी अनुपालना में विभाग द्वारा आई एम शक्ति उड़ान योजना बनाई गई है।

सुशासन सूचकांक, 2021 में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- 25 दिसंबर, 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया, जिसमें ग्रुप 'बी' में राजस्थान को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जीजीआई-2021 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों- समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में बाँटकर रैंकिंग दी गई है। जीजीआई-2021 तैयार करने के लिये 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है।
- राजस्थान ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.884 स्कोर के साथ ग्रुप 'बी' में द्वितीय रैंक प्राप्त किया है, वहीं मध्य प्रदेश ने इस ग्रुप में प्रथम रैंक प्राप्त किया है तथा गुजरात ने ग्रुप 'ए' में प्रथम रैंक प्राप्त की है।
- राजस्थान ने पिछले सूचकांक (2019) की तुलना में अपने स्कोर में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछली बार इसका स्कोर 4.80 था, जो अब बढ़कर 4.88 हो गया है।
- सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है, जिसमें राजस्थान की रैंकिंग तथा स्कोर निम्नलिखित हैं-

क्षेत्र	राजस्थान की रैंकिंग	स्कोर
1. कृषि और संबद्ध क्षेत्र	चतुर्थ	0.501
2. वाणिज्य एवं उद्योग क्षेत्र	5वीं	0.638
3. मानव संसाधन विकास क्षेत्र	7वीं	0.398
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र	6वीं	0.249
5. सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र	8वीं	0.525
6. आर्थिक शासन क्षेत्र	8वीं	0.290
7. समाज कल्याण एवं विकास	तृतीय	0.606
8. न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा	प्रथम	0.417
9. पर्यावरण क्षेत्र	प्रथम	0.377
10. नागरिक केंद्रित शासन	प्रथम	0.883

प्रदेश के 5 प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

- 27 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के 5 प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आकर्षक लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल गोविंद देव जी मंदिर परिसर स्थित जयनिवास उद्यान, मेड़ता में मीराबाई स्मारक, चित्तौड़गढ़ के विश्वविख्यात दुर्ग, धौलपुर के मचकुंड में आकर्षक लाइट एंड साउंड शो तथा जैसलमेर की ऐतिहासिक गड़सीसर झील में लेज़र वाटर शो का लोकार्पण किया।
- केंद्रीय संस्कृति राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से देशी एवं विदेशी सैलानियों को राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के पर्यटन विकास को गति मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिये सरकार ने 500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाने का अहम निर्णय लिया है। इस कोष से पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, उनके संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत ब्रांडिंग जैसे कार्य किये जाएंगे।
- धार्मिक, वाइल्ड लाइफ, ट्राईबल, डेजर्ट पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिये नए-नए सर्किट जोड़ने के साथ ही सभी प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर विकास के कार्य किये जा रहे हैं।
- राज्य के मुख्य शासन सचिव पर्यटन, गायत्री राठौड़ ने बताया कि पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश में स्वीकृत 8 प्रोजेक्ट्स में से 5 लाइट एंड साउंड शो तथा लेज़र वाटर शो का लोकार्पण किया गया है। शेष 3 स्थानों पर भी जल्द ही ये शो शुरू होंगे।

- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड-2021 में बेस्ट आईकोनिक लैंडस्केप डेस्टीनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टीवल डेस्टीनेशन अवार्ड, ट्रैवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड-2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य तथा सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टीनेशन सहित कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

आशा पाराशर के कथा संग्रह 'आदमखोर' का विमोचन

चर्चा में क्यों?

- 27 दिसंबर, 2021 को जयपुर की कलानेरी आर्ट गैलरी में आशा पाराशर के पहले कहानी संग्रह 'आदमखोर' का विमोचन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. शारदा कृष्ण ने कहा कि लेखिका आशा पाराशर ने अपनी कहानियों में समाज के जिन विषयों को उठाया है, वह प्रशंसनीय है।
- वरिष्ठ रंगकर्मी और लेखक डॉ. अशोक राही ने कहा कि आशा पाराशर की कहानियाँ समाज का आईना हैं। कथा संग्रह की प्रत्येक कहानी प्रभावित करती है और जीवन के प्रति लेखिका के एक बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण को सामने लाती है। ये कहानियाँ पाठकों को मानसिक रूप से उद्वेलित करती हैं और समाज की वास्तविकताओं तथा विसंगतियों के बारे में सोचने के लिये मजबूर करती हैं।
- हिन्दी प्रचार संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अखिल शुक्ला ने कहा कि सामाजिक संदेश देती लेखिका की कहानियाँ जीवन के विभिन्न चरित्रों की वास्तविकता को प्रदर्शित करने वाली हैं। सभी कहानियाँ पठनीय और संदेशपरक हैं।
- वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. आशा शर्मा ने कहा कि सभी कहानियाँ भावप्रवण हैं और मानवीय संवेदनाओं को जगाने वाली हैं। समाज के किसी-न-किसी गंभीर विषय को उठाती ये कहानियाँ लेखिका की सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
- लेखिका आशा पाराशर ने अपनी पुस्तक के बारे में बताया कि अपनी कहानियों में उन्होंने शहरी मध्यवर्ग की कथाओं को ज़िंदा करने की कोशिश की है। उनकी कहानियाँ आम आदमी की संक्षिप्त आत्मकथाएँ हैं। उन्होंने बताया कि इस संग्रह में कुल 23 कहानियाँ हैं। हिन्दी कहानियों की यह उनकी प्रथम पुस्तक है।

नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में राजस्थान

चर्चा में क्यों?

- 27 दिसंबर, 2021 को सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 2019-20 के लिये अपने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया, जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई। इसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में राजस्थान 16वें स्थान पर है, वहीं केरल शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट को तीन भागों में बाँटा गया था- बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। छोटे राज्यों में मिज़ोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा जबकि नागालैंड सबसे नीचे रहा।
- नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद दादरा और नगर हवेली दूसरे नंबर पर तथा दिल्ली तीसरे नंबर पर है।
- बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में राजस्थान 41.33 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 16वें स्थान पर है। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले, तमिलनाडु 72.42 स्कोर के साथ दुसरे एवं तेलंगाना 69.96 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
- नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं।

नोट :

शरद महोत्सव-2021

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आबू पर्वत नगर पालिका के शरद महोत्सव-2021 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने माउण्ट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील पर गांधी वाटिका में गांधीजी की प्रतिमा का अनावरण तथा महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया और झील के किचन गार्डन पर पार्किंग एवं टेरेस गार्डन का शिलान्यास भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि माउण्ट आबू राजस्थान का एक मात्र हिल स्टेशन है। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान की देश और दुनिया में अनूठी पहचान है। यहाँ की मनभावन संस्कृति, किलों, महलों, बावड़ियों तथा वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट आदि से जुड़े आकर्षक स्थलों को देखने बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं।
- उन्होंने कहा कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने के लिये पहली बार 500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष बनाया गया है। इस कोष से पर्यटक स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास, उनके संरक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मज़बूत ब्रॉन्डिंग जैसे कार्य किये जाएंगे।
- पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिये राजस्थान को इंडिया टूडे टूरिज़्म अवार्ड 2021 में बेस्ट आईकोनिक लैंडस्केप डेस्टीनेशन अवार्ड, बेस्ट फेस्टीवल डेस्टीनेशन अवार्ड और ट्रेवल एंड लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्डस् 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के साथ सर्वश्रेष्ठ वेडिंग डेस्टीनेशन अवार्ड और कोंडेनास्ट ट्रेवलर अवार्ड-2021 में बेस्ट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप एवं रनरअप बेस्ट लेज़र डेस्टिनेशन अवार्ड मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान पुलिस विज़न-2030 पुस्तक का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस विज़न-2030 पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 के विज़न को लेकर प्रकाशित की गई, यह पुस्तक पुलिस को और अधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को प्रेरित करेगी।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पुलिस के आधुनिकीकरण की दिशा में राज्य सरकार निरंतर नवाचार कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
- पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर ने बताया कि इस पुस्तक में राजस्थान पुलिस को वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार करने एवं जनता को बेहतर पुलिसिंग देने के संबंध में विज़न प्रस्तुत किया गया है।
- उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो आगामी वर्षों में पुलिस विभाग के व्यापक एवं समग्र विकास के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

राणा प्रताप सागर पन विद्युतगृह

चर्चा में क्यों ?

- 29 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की 43 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 1 को सिंक्रोनाइज कर पुनः विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया। पूर्ण क्षमता से संचालित होने पर इस इकाई से प्रतिदिन 10.32 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों की साझा चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1968 में चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर स्थापित 172 मेगावाट (43 मेगावाट की 4 यूनिट) क्षमता के पन बिजलीघर का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। वर्ष 1968 में स्थापना के पश्चात् इस बिजलीघर से 2,365 करोड़ रुपए यूनिट की सबसे सस्ती एवं हरित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है।
- उल्लेखनीय है कि चंबल नदी में 14 सितंबर, 2019 को उत्पन्न हुई भीषण जल विभीषिका में पन बिजलीघर की चारों इकाइयाँ पूर्ण रूप से जलमग्न हो गई थी। 51 वर्ष पुरानी इन इकाइयों से पुन: विद्युत उत्पादन हेतु पुनरुद्धार योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसमें 5-6 वर्षों तक इकाइयों के बंद रहने का अनुमान बताया गया था।
- राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर.के. शर्मा ने इस उपलब्धि पर कहा कि निगम के कुशल अभियंताओं की देखरेख एवं अनवरत मेहनत के कारण ही इस इकाई से पुन: विद्युत उत्पादन शुरू किया गया है। उन्होंने शीघ्र ही चतुर्थ इकाई को भी अतिशीघ्र पुन:संचालन करने के निर्देश दिये।

नोट :